THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI SURESH PRABHU): (a) to (d) With reference to the news item, it is stated that a Household Survey of Health Care Utilization and Expenditure carried out by the National Council of Applied Economic Research (NARER) in 1993 showed that 62% of the cases in rural areas and 60% of the cases in urban areas, inpatient treatment was sought in public sector hospitals. However, about 52% in rural areas and 59% in the urban areas sought ambulatory care in private sector facilities. For providing generally free health care services, there are an estimated 4579 hospitals at the district and sub-district levels accounting for about 65% of the total beds in the country established in the public sector. A National Illness Assistance Fund has been recommended to be set up by the State Governments to enable financial assistance to be given to patients, below the poverty line, suffering from life threatening diseases.

Health being a state subject under the Constitution, the provision of health services is the responsibility of the State Governments. Central Government continues to support the State Governments in controlling specific diseases through the implementation of National Disease Control Programmes under which treatment is extended free of charge.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

आठवीं पंचवर्षीय योजना में उर्वरक संयंत्रे के विस्तार का लक्ष्य

1974. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों के विस्तार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस संबंध मं लक्ष्य प्राप्ति की तथ्यात्मक स्थिति क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान देश में उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित आकलन भी किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु यूरिया की उत्पादन वृद्वि के लिए अनुमानत: कितनी धनराशि की आवश्यकता हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए के पटेल) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सार्वजानिक/सहकारी क्षेत्र में नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) की विजयपुर तथा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर काआपरेटिव लि. (इफ्को) के आवंला स्थित उर्वरक संयंत्रों के विस्तार की परिकल्पना की गई थी। इन संयंत्रों की क्षमता दुगुने होने के परिणामस्वरूप 2026 करोड़ रूपए की कुल लागत पर यूरिया की क्षमता में 14.52 लाख मी. टन प्रतिवर्ष की वृद्वि हुई हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान उर्वरक पोषकों के उत्पादन का अनुमान 111.55 लाख मी. टन लगाया गया हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने हेतु 23.28 लाख मी. टन यूरिया का आयात किया गया। वर्तमान अनुमानों के अनुसार 7.26 लाख मी. टन के वार्षिक क्षमता वाले ग्रास-रूट यूरिया संयंत्र के लिए लगभग 1570 करोड़ रूपए के निवेश की आवश्यकता हैं।

मंत्री जी के व्यक्तिगत स्टाफ का संसद सदस्यों के साथ व्यवहार

1975. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के निजी स्टाफ और अतिरिक्त निजि सचिव द्वारा अपने अशोभनीय व्यवहार से संसद सदस्यो की गारिमा को ठेस पहुंचाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होने सांसदों की गरिमा को बरकरार रखने के लिए राज्य मंत्री को कोई निर्देश दिया हैं;

(ग) क्या उन्होने इस संबंध में दोषी पाए गए अतिरिक्त निजी सचिव और स्टाफ को बदलने के लिए राज्य मंत्री को आदेश जारी किए है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) और (ख) वैयक्तिक कर्मचारियों को सभी के साथ, खासतौर से माननीय संसद सदस्यों और